

इलेक्ट्रॉनिक घटक वनिर्माण योजना (ECMS)

स्रोत: इकोनॉमिक्स टाइम्स

भारत की इलेक्ट्रॉनिक घटक वनिर्माण योजना (ECMS) को 13 अरब अमेरिकी डॉलर के नविश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो इसके लक्ष्य से लगभग दोगुना है। MSME की 60% भागीदारी के साथ, इस योजना से घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिला, आयात पर निर्भरता कम होगी और प्रत्यक्ष रूप से 1.41 लाख नौकरियों का सर्जन होगा, जिससे भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक केंद्र बनने की दशा में और सफलता मिलेगी।

- **परिचय:** भारत सेमीकंडक्टर मशिन के पूरक के रूप में अप्रैल 2025 में शुरू की गई ECMS का लक्ष्य **घरेलू मूल्य संवर्धन (DVA)** को बढ़ावा देकर और भारतीय फर्मों को **वैश्विक मूल्य शृंखलाओं (GVC)** से जोड़कर तैयार माल और चपि निर्माण से आगे बढ़कर भारत की इलेक्ट्रॉनिक मूल्य शृंखला का सुदृढीकरण करना है।
 - ECMS ऑटोमोबाइल, बजिली और औद्योगिक क्षेत्रों के साथ क्षेत्रीय संबंधता (आपूर्ति शृंखला में समान स्तर के प्रतिभागियों के बीच संबंध एवं सहयोग) में सहायक है।
- **योजना अवधि:** 6 वर्ष (1 वर्ष की उत्पादन/निर्माण पूर्व अवधि) अर्थात् वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2031-32 तक।
- **प्रोत्साहन संरचना:** ECMS के अंतर्गत **टर्नओवर-लकिड, कैपेक्स-लकिड या हाइब्रिड राजकोषीय प्रोत्साहन** प्रदान किया जाएगा, जिसमें टर्नओवर और कैपेक्स दोनों प्रोत्साहनों का एक हिस्सा **रोज़गार सृजन से संबंधित** है।
 - प्रोत्साहन **फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व** के आधार पर उन कंपनियों को प्रदान किया जाएगा जो प्रारंभिक उत्पादन के लिये तैयार हैं।
- **महत्त्व:** इलेक्ट्रॉनिक्स भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक क्षेत्र है और देश वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता है। उत्पादन-संबंध प्रोत्साहन (PLI) और सेमीकंडक्टर पहलों के साथ, ECMS वर्ष 2030-31 तक 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स वनिर्माण इकोसिस्टम का निर्माण किया जाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

और पढ़ें: इलेक्ट्रॉनिक्स वनिर्माण की संभावनाओं को उजागर करना